



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938

No. 72]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 23 फरवरी, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2017

सं.सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/036.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15अख, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अक तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19अक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 में, -

- (I) विनियम 4 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

"(2) उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल आवेदन पर विचार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि उप-विनियम (1) में निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन दाखिल न किए जाने का पर्याप्त कारण था और आवेदन के साथ विलंब (देरी) के लिए माफी हेतु आवेदन भी किया गया है तथा अनुसूची - I के भाग-ख में यथा निर्धारित अप्रतिदेय (नॉन-रिफंडेबल) फीस भी लगाई गई है :

परंतु यह कि जहाँ आवेदन उप-विनियम (1) में निर्धारित अवधि की समाप्ति से साठ कलेंडर दिनों के पश्चात् दाखिल किया जाए, वहाँ आवेदक द्वारा अदा की जाने वाली निपटारे की रकम में, उप-विनियम (1) में निर्धारित अवधि के समाप्त होने से लेकर दाखिल किए जाने की तारीख तक, छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाकर बढ़ोतरी कर दी जाएगी।"

- (II) विनियम 5 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"परंतु यह कि असाधारण परिस्थितियों में, जैसे अभिकथित (कथित) चूक होने के बाद समय बीत गया हो, आवेदक के खिलाफ सबूत (साक्ष्य) की उपयुक्तता, आदि, तथा ऐसी अतिरिक्त फीस और/या निपटारे की रकम पर लगाए गए ब्याज (पहले किए गए आवेदन को नामंजूर किए जाने की तारीख से निपटारे की रकम अदा किए जाने की तारीख तक) के भुगतान के अध्यक्षीन (जैसी उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश की जाए) ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।"

- (III) विनियम 6 में, उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"परंतु यह कि कार्यवाहियों की अगली अवस्था (जिसका उल्लेख अनुसूची - II में दी हुई सारणी I में है) में, यदि आवेदक पर्याप्त आधार दे, तथा ऐसी अतिरिक्त फीस और/या निपटारे की रकम पर लगाए गए ब्याज (पहले किए गए आवेदन को वापस लिए जाने की तारीख से निपटारे की रकम अदा किए जाने की तारीख तक) के भुगतान के अध्यक्षीन (जैसी उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश की जाए) ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।"

- (IV) विनियम 8 में, उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

"(4) विनियम 3 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित आवेदन फीस, विनियम 4 के उप-विनियम (2) में यथा उल्लिखित विलंब (देरी) के लिए माफी हेतु किए गए आवेदन के साथ दी जाने वाली अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस और विधिक खर्चें, यदि कोई हों, (जो निपटारे की रकम का भाग हों) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की साधारण निधि (जनरल फंड) में जमा किए जाएंगे।"

(V) विनियम 14 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

"(3) जहाँ पैनल निपटारे के आदेश को पारित किए जाने की सिफारिश को स्वीकार कर ले, वहाँ आवेदक,-

(क) माँग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह कलेंडर दिनों के भीतर निपटारे की रकम [जो निपटारे की शर्तों आदि (के निबंधनों) का भाग हो] प्रेषित करेगा, और यह अवधि पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध (रिकॉर्ड) किए जाएँगे, पंद्रह कलेंडर दिनों की अवधि (अवधियों) तक बढ़ाई जा सकेगी :

परंतु यह कि किसी भी दशा में ऐसा धन-प्रेषण माँग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से नब्बेवें कलेंडर दिन के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहाँ निपटारे की रकम माँग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस कलेंडर दिनों के पश्चात् और ऐसी प्राप्ति से नब्बेवें दिन को या उससे पूर्व प्रेषित की जाती है, वहाँ आवेदक द्वारा अदा की जाने वाली निपटारे की रकम में, माँग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से निपटारे की रकम अदा किए जाने की तारीख तक, छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाकर बढ़ोतरी कर दी जाएगी; और/या

(ख) उसे दिए गए समय के भीतर, निपटारे की अन्य शर्तों आदि, यदि कोई हों, को पूरा करेगा / का पालन करने का वचन लिखित रूप में देगा ।"

(VI) विनियम 20 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ड) में शब्दों और चिह्न "निपटारे की रकम विप्रेषित नहीं करता या निपटारे की रकम के भुगतान में विलंब करता है और/या वचनों और अधित्यजनों" के लिए, शब्द, चिह्न और अंक "विनियम 14 के उप-विनियम (3) के खंड (क) में निर्धारित अवधि के भीतर निपटारे की रकम प्रेषित नहीं करता और/या वचन तथा अधित्यजनों (वेवर्स)" प्रतिस्थापित हो जाएँगे ।

(VII) अनुसूची - I में, भाग-ख में, मौजूदा मद के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा -

"प्रत्येक आवेदक दस हजार रुपये की प्रोसेसिंग फीस अदा करेगा और माफी हेतु किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ दो हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, जिनका भुगतान 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड' के पक्ष में लिखे गए माँग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से या बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से किया जाएगा ।"

(VIII) अनुसूची - II में, अध्याय I में,-

(1) मद 6 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्,-

"सूचक राशि (आईए) की गणना प्रत्येक आवेदक के लिए की जाएगी। उस मामले में, जहाँ एक ही वाद हेतुक (कॉज़ ऑफ़ एक्शन) से उद्भूत चूक (डिफॉल्ट) के संबंध में अनेक आवेदक आवेदन करते हैं, वहाँ सूचक राशि (आईए) की गणना प्रत्येक आवेदक के लिए, लागू फार्मूले के अनुसार की जाएगी, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर जहाँ यह माना जा सके कि आवेदकों का संयुक्त और पृथक दायित्व है,-

- (क) अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों के अधीन अर्जनकर्ता और सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्ति (पीएसी);
- (ख) निदेशकों (डायरेक्टर्स) के मामले में, जहाँ कुछ करके या न करके, उन्होंने कंपनी के किसी कार्य में केवल सामूहिक भूमिका निभाई हो;
- (ग) व्यक्तियों का कोई अन्य समूह, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जैसी आंतरिक समिति / उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति सिफारिश करे।"

(2) मौजूदा मद (12), मद (13) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगी;

(3) मद (11) के पश्चात् और मद (13) से पूर्व, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

"(12) निपटारे की सूचना (नोटिस) : जिन मामलों में निपटारा अपवर्जित है, उन मामलों से भिन्न मामलों में, कारण बताओ संबंधी सूचना जारी करने से पहले निपटारे की सूचना (नोटिस) जारी की जा सकेगी, जिसके अंतर्गत आरोपों के सार और संभावित कार्रवाइयों का उल्लेख होगा, ताकि निपटारे का आवेदन, निपटारे की सूचना (नोटिस) की प्राप्ति से पंद्रह कलेंडर दिनों के भीतर, दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

निपटारे की सूचना (नोटिस) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पास नोटिसी के खिलाफ की जाने वाली प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई में परिवर्तन करने की शक्ति होगी और सूचना (नोटिस) निपटारे की मांग का या किसी प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई से बचने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।"

(IX) अनुसूची - II में, अध्याय II में, मद 1 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात् -

"1. (क) जहाँ न्यायनिर्णायक अधिकारी (एओ) आवेदक पर पहले ही शास्ति लगा चुका हो, वहाँ 'बी' इन मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) के अनुसार निकाली गई राशि

या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति (पेनल्टी), जो भी अधिक हो, के बराबर होगी;

(ख) यदि एक ही वाद हेतुक (काँज़ ऑफ़ एक्शन) से उद्भूत एक से अधिक कार्यवाहियाँ आवेदक के खिलाफ शुरू की गई हों, तो सूचक राशि (आईए) में 15% तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी;

(ग) ऐसे मामलों में जहाँ पूर्णकालिक सदस्य या नामनिर्दिष्ट सदस्य (डीएम) ने आवेदक को विवर्जित करने या निलंबित करने के निदेश जारी किए हों, वहाँ आरएएफ के अंतर्गत सारणी III के अनुसार वाई के मान (वैल्यू) पर विचार किया जाएगा।"

(X) अनुसूची - II में, अध्याय III में, सारणी I निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात् -

"सारणी I - पीसीएफ

आवेदन किए जाने के समय कार्यवाही (कार्यवाहियों) की अवस्था		पीसीएफ का मान (वैल्यू)
क.	स्वेच्छा से या स्वप्रेरणा से सूचना दी गई*	0.65
ख.	कारण बताओ संबंधी सूचना (नोटिस) जारी होने से पहले [जिसमें निपटारे की सूचना (नोटिस) की प्राप्ति से पंद्रहवें कलेंडर दिन या उससे पूर्व दाखिल किए गए आवेदन शामिल हैं]	0.75
ग.	एक ही वाद हेतुक (काँज़ ऑफ़ एक्शन) में किसी लंबित कार्यवाही के संबंध में कारण बताओ संबंधी पहली सूचना (नोटिस) जारी होने के पश्चात् [जिसमें निपटारे की सूचना (नोटिस) की प्राप्ति से पंद्रहवें कलेंडर दिन के पश्चात् दाखिल किए गए आवेदन शामिल हैं]	0.85
घ.	नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (डीए) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् कार्यवाही लंबित	0.9
ङ.	यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी या नामनिर्दिष्ट सदस्य या पूर्णकालिक सदस्य द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् कार्यवाहियाँ लंबित	1.10
च.	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) या उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् कार्यवाहियाँ लंबित	1.20

*कपटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित मामलों पर विचार अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) के दौरान प्रदान किए गए सबूत (साक्ष्य), प्रदान की गई जानकारी और सहायता को ध्यान में रखते हुए किया जा सकेगा, अन्यथा ख. लागू होगा।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./439/16(69 जेड बी)]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/37/50 द्वारा, 9 जनवरी 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 तत्पश्चात् :-
 - (1) 15 सितम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/08/1491, द्वारा
 - (2) 29 अगस्त 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/010, द्वारा संशोधित हुए थे।

.....

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 23rd February, 2017

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**(SETTLEMENT OF ADMINISTRATIVE AND CIVIL PROCEEDINGS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2017**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/036.—In exercise of the powers conferred under section 15JB of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, section 23JA of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and section 19-IA of the Depositories Act, 1996 read with section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014,—

(I) In regulation 4, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the panel of whole time members may consider the application, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within the period specified in sub-regulation (1) and it is accompanied with an application for condonation of delay and non-refundable fees as specified in Part-B of the Schedule-I.

Provided that where the application is filed after sixty calendar days from the expiry of the period specified in sub-regulation (1), the settlement amount payable by the applicant shall be increased by a levy of simple interest at the rate of six per cent, per annum, from the expiry of the period specified in sub-regulation (1) till the date of filing."

(II) In regulation 5, in sub-regulation (1), in clause (b) the following proviso shall be inserted, namely-

"Provided that such an application may be considered in exceptional circumstances, such as the lapse of time since the commission of the alleged default, the weight of evidence against the applicant, etc and subject to the payment of such additional fees and/or interest on the settlement amount from the date of rejection of the earlier application till the date of payment of the settlement amount, as may be recommended by the high powered advisory committee."

(III) In regulation 6, in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely-

"Provided that such an application may be considered at the next stage of proceedings, as indicated in Table I in Schedule-II, if the applicant makes out adequate grounds and subject to payment of such additional fees and/or interest on the settlement amount from the date of withdrawal of the earlier application till the date of payment of the settlement amount, as may be recommended by the high powered advisory committee."

(IV) In regulation 8, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely-

"(4) The application fee referred to in sub-regulation (2) of regulation 3, the additional processing fee accompanying the application for condonation of delay as referred to in sub-regulation (2) of regulation 4 and the legal costs, if any, forming part of the settlement amount shall be credited to the Securities and Exchange Board of India General Fund."

(V) In regulation 14, for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely -

"(3) Where the panel has accepted the recommendation to pass a settlement order, the applicant shall,-

(a) remit the settlement amount forming part of the settlement terms, not later than fifteen calendar days from the date of receipt of the notice of demand, which may be extended by the panel of whole time members for reasons to be recorded, by a period(s) of fifteen calendar days.

Provided that in no case shall such remittance be accepted after the ninetieth calendar day from the date of the receipt of the notice of demand.

Provided further that where the settlement amount is remitted after thirty calendar days from the date of receipt of the notice of demand and on or before the ninetieth day from such receipt, the settlement amount payable by the applicant shall be increased by the levy of simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of receipt of the notice of demand till the date of payment of the settlement amount; and/or

(b) fulfil/undertake in writing to abide by, the other settlement terms, if any, within the time provided to the applicant."

(VI) In regulation 20, in sub-regulation (1), in clause (e) the words "or delays the payment of settlement amount" shall be substituted with the words, symbols and numbers, "the settlement amount within the period specified in clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 14"

(VII) In Schedule- I, in Part-B, for the existing item the following shall be substituted, namely-

"Every applicant shall pay processing fees of ten thousand rupees and every application for condonation shall be accompanied with additional processing fees of two thousand rupees, by way of a demand draft in favour of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai or by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI."

(VIII) In Schedule- II, in Chapter I, -

(1) item 6 shall be substituted with the following, namely-

"The IA is to be calculated for each applicant. In a case where multiple applicants apply in respect of a default arising from the same cause of action, the IA will be calculated for each applicant, as per the applicable formula except in the following cases where the applicants may be considered to have joint and several liability,-

(a) the acquirer and persons acting in concert (PAC) under the Takeover Regulations;

(b) in case of directors, where by reason of commission or omission they have only acted collectively for an act of the company;

(c) any other group of persons, based on the facts and circumstances of each case, which the IC/HPAC may so recommend."

- (2) the existing item (12) shall be re-numbered as item (13);
 (3) after item (11) and before item (13) the following item shall be inserted, namely,-

"(12) Settlement Notice: Except in cases which are excluded from settlement, a settlement notice indicating the substance of the charges and probable actions may be issued in advance of the notice to show cause so as to afford an opportunity to file a settlement application, within fifteen calendar days from receipt of the settlement notice.

Notwithstanding anything contained in the settlement notice, the Board shall have the power to modify the enforcement action to be brought against the noticee and the notice shall not confer any right to seek settlement or avoid any enforcement action."

(IX) In Schedule- II, in Chapter II, item 1, shall be substituted with the following, namely-

- "1. (a) Where the AO has already awarded penalty to the applicant, then 'B' shall be equal to the amount calculated by these guidelines or the penalty awarded by the AO, whichever is higher;
 (b) In case more than one proceeding arising from the same cause of action has been initiated against the applicant, the IA shall be increased by 15%;
 (c) In cases where the WTM or DM has issued directions debarring or suspending the applicant, the RAF shall take into account the value of Y as per Table III."

(X) In Schedule- II, in Chapter III, Table I shall be substituted with the following, namely-

"TABLE I-PCF

STAGE OF THE PROCEEDING(S) WHEN THE APPLICATION IS MADE		VALUE OF PCF
a.	Voluntary or suo-moto intimation matters *	0.65
b.	Pre- issue of the notice to show cause (including applications filed on or before 15th calendar day from the receipt of the settlement notice)	0.75
c.	Post-issue of the first notice to show cause pertaining to any pending proceeding in the same cause of action (including applications filed after 15th calendar day from the receipt of the settlement notice)	0.85
d.	Proceeding pending after the submission of the report by the DA	0.9
e.	Proceedings pending after passing of the order by the AO or DM or WTM, as the case may be	1.10
f.	Proceedings pending after the passing of the order by the SAT or High Court	1.20

***Cases relating to fraudulent and unfair trade practices may be considered taking into account the evidence, information and assistance provided during the course of investigation, otherwise b. will apply."**

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./439/16 (69 ZB)]

Footnote:

1. The SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 were published in the Gazette of India on January 09, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/37/50.
2. The SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 were subsequently amended on:-
 - (1) 15th September, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/08/1491.
 - (2) 29th August, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. LAD-NRO/GN/2016-17/010.